

स्पष्टआवाज़



लखनऊ

बुधवार, 6 मार्च, 2024 वर्ष : 20, अंक : 250 पृष्ठ : 12

www.spashtawaz.com मूल्य : ₹ 3

लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, लिलितपुर से प्रकाशित



Stallion Honda

MG Autosales Pvt. Ltd.

Ayodhya Road, Lucknow

Top Reasons to Buy All New Honda Elevate

- World famous iVTEC petrol engine
- Best in segment High Ground Clearance of 220 mm
- 3 Year unlimited KMs of warranty & also 10 Years Any Time Warranty
- Level-2 ADAS ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM
- Best in class cabin space with 2650 mm wheelbase and 458 Ltrs of Boot Space
- Honda Connect with Smart Watch and Alexa connectivity.

Showroom (1S) :

CP 5, Vikrant Khand, Gomtinagar, Ayodhya Road, Lucknow - 226010

Sales: +91 7897222000, +91 18009809995 | Service: +91 8009090093

Service (3S) :

Anaura, After Indira Canal, Ayodhya Road, NH-28, Lucknow

ELEVATE
Starts from ₹11 57 900*HONDA
The Power of Dreams[/stallionhonda](https://www.facebook.com/stallionhonda)

आर.सी.जे. ज्वेलर्स

(आर.सी.ज्वेलर्स)

सारांश बाजार, कुर्सी रोड, अलीगंज

लखनऊ निकाट आर्ट समाज नारद

गोल मार्फत, गहनगढ, लखनऊ

बान गली गली, घौंक, लखनऊ

गो. - 8299567219

9455555965, 9415133977

संक्षिप्त आवाज



किसानों को मुफ्त विजली का तोहफा

• होमगार्ड का डीए बढ़ा, शारीर बेचने के नियमों में होगा बदलाव, कैबिनेट ने 29 प्रस्ताव मार्जुर



लखनऊ (स्पष्ट आवाज़)। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की। जिसमें 29 प्रस्ताव मार्जुर किए गए। इनमें तहत किसानों को फीट विजली दी जाएगी। वहाँ, होमगार्ड के भेजन भरा को 30 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदिलनाथ की अधीक्षण में मंगलवार के बैठक में यह फैसला लिया गया। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताम शाही और उर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रत्यक्षों को बताया कि योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2023 ने जिनी नलकूप पर पहुंचता है। इस तरह लगभग लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है। प्रति किसान यदि पांच सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6-7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते। उहाँने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अतिकृष्ण विशेष व्यक्तियों के लिए अतिकृष्ण गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री के सिविल लाइसेंस क्षेत्र में 10000 वर्ष मीटर नवल खुम मार्जुर संपत्ति विभाग को स्थानांतरित करता है। इसके लिए योजना विभाग को नियंत्रण दिया गया।

इनकृष्णवेशन सेंटर पर खर्च होगा। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण थार में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से बिडर के चयन पर मुहर लगा दी गई। प्रधानमंत्री में चाचाबाग से बसंत कुंज तक चलाने पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत चाचाबाग से बसंतकुंज तक व्यक्तियों के लिए अतिकृष्ण गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री के सिविल लाइसेंस क्षेत्र में 10000 वर्ष मीटर नवल खुम गार्जुर संपत्ति विभाग को स्थानांतरित करता है। इसके लिए योजना विभाग को नियंत्रण दिया गया।

एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकास करेगी सरकार

कैबिनेट के समाने आज उद्योगों को जीमीन देने के उद्देश्य से प्राधिकरणों में लैंड पूर्णी नीति के प्रस्तावत भी भी मंजुरी दी गई। योगी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) विकास करने का निर्णय लिया है। मंत्री एवं शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उप्र में राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ (एनसीआर) को विकास करने के लिए एए प्रस्ताव को मंजुरी भिल गई है। छह जिलों को मिलाकर एनसीआर बनाया। इसके लिए लखनऊ से सटे हरदाई, सीतापुर, उत्तराव, रायबरेली और बाराबरी के जिलों का तोड़ी से विकास भवाने गया।

एसबीआई को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही सरकार नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रिमंडल खड़ा ने मंगलवार को आरेष लगाया कि सरकार अपने संसदीय लेनदेन को छिपाकर और चुनावी बॉर्ड से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले को नामानुसार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। पिछले महीने अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई के छार्मिंग तक समय बढ़ाव दिलाया था। इसके लिए लखनऊ से सटे हरदाई, सीतापुर, उत्तराव, रायबरेली और बाराबरी के जिलों को विकास प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

सरकार बनने पर पैपर लीक गठजोड़ प्राथमिकता से खत्म करेंगे

रहा है। उहाँने कहा कि लापत्तवाह सरकार, छष्ट अधिकारी, नकल माफिया और नियंत्रित प्रिंटिंग प्रेसों के अपाराधिक कांगड़ों को खत्म कर हर स्तर पर जाचाबदी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। जब मैंने छात्रों से जाचाचीत की तो उहाँने मुझे बताया कि पैपर लीक की तीन मुख्य बजह हैं। बिहारी हुआ सरकारी तंत्र, नियंत्रित प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड़ुक बन चुके उत्तर प्रदेश ही नहीं देशभर में युवाओं के लिए अधिकारी योजना। कृशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। रिसर्च की भी सुविधा मिलाया जाएगा। दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय तैयार होगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा। प्रेसके चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानगढ़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनकृष्णवेशन सेंटर लगाया जाएगा।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल

राज मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

के प्राथमिक सेवान (ताज ईस्ट गेट से मनः कामेश्वर) पर यात्री सेवा का

शुभारंभ

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री द्वारा

(वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)

गरिमामयी उपरिवर्ति

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल

उत्तर प्रदेश

योगी आदिलनाथ

मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश

हरदीप सिंह पुरी

मंत्री, प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार

वैदी रानी मौर्य

मंत्री, महिला कल्याण, बाल विकास

एवं पुष्टाहर, उत्तर प्रदेश

धर्मवीर प्रजापति

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार एवं होमपाइस, उत्तर प्रदेश

राजु कुमार चाहर

सासद, फतेहपुर सीकरी

सासद, राज्य सभा

नवीन जैन

संक्षिप्त समाचार

15 दिन बीते, किसानों को नहीं मिली सहायता
भ्रांता सुप्रेरपुर। ओलावृष्टि के 15 दिन गुजरने के बाद किसानों को सरकारी सहायता का एक धेला अभी तक नसीब नहीं हुआ है। ब्लॉकें के 40 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हैं। इन गांवों में 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च के मध्य तीन बार ओलावृष्टि हुई है। कृषि विभाग निरीक्षण के दौरान कह चुका है कि किसान बुरी तरह से तबाह हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश है कि ओला प्रभावित किसानों को 24 घंटे में मदद मुहूर्त कराई जाए। लेकिन यह आदेश यहाँ नदारत है। ओलावृष्टि के 15 दिन गुजर जाने के बाद किसानों को एक धेला नसीब नहीं हुआ है। ओला प्रभावित बांक, बिलहड़ी, बांकी, नदरार, स्वामा खुर्द, स्वामा बुर्ज, कम्हुपुर, मोराकांदर, सहुपुर, उजेन्डी, कलौंदी जा, पाथिया, दरियापुर, नूँझा, सौंखा, देवगंग, पंचरी, पारा ऐरा, पारिखोरा, मौहर, अतरैया, टेढ़ा, पचवाहा बुर्ज, बस्ता, भारा, सुरील बुर्ज आदि के ग्राम प्रधानों ने बताया कि अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। सर्वे के बाद किसानों से लेखाल खतोनी आधार कार्ड आदि मांग रहे हैं। इसके बाद ही सहायता मिलने की उम्मीद है।

एमटीएम घोटाले का हुआ खुलासा

भ्रांता सुप्रेरपुर। बीते दो मार्च को प्रभारी खड़ विकास अधिकारी शार्तुन कुमार सिन्हसिनवार ने ग्राम पंचायत कैथी के कोपेजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रभारी बीड़ीओं को पंजीकृत 560 छात्र छात्राओं के सापेक्ष 191 बोजूद मिले थे। जबकि मध्यांश भोजन रजिस्टर में प्रधानाध्यापक के दिनेश चंद्र ने 303 छात्र छात्राओं को भोजन करना दर्शाया था। इसकी रिपोर्ट बीड़ीओं ने जिलाधिकारी राहुल पांडेय को भेजी थी। बीड़ीओं की इस कार्यवाही से शिक्षकों में हड्डकंप मचा हुआ है।

मौसम की करवट, वायरल फीवर ने पासारे पैर

भ्रांता सुप्रेरपुर। मौसम के बदलाव का असर मानव जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है। ओलावृष्टि एवं बारिंग के बाद वायरल बुखार में तेजी के साथ पैर पसारे हैं। मंगलवार को ओपीडी में जौजूद चिकित्सक डॉ तरुण पाल, डॉ परवेज कादरी, डॉ शमा परवीन ने बताया कि मौसम बदलाव से वायरल बुखार में जौजूद हुआ है। ओपीडी में अचानक सैकड़ों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जौजूद वायरल को 234 तथा मंगलवार को 500 जौजूदों का बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि वायरल बुखार सर्वाधिक बच्चे, बृद्ध शिक्षक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायरल बुखार से बचने के लिए लोगों को साफ उत्तोला पानी और हल्का सुपाया भोजन ग्रहण करना चाहिए और सुबह-शाम पड़ने वाली सर्दी से भी बचाव की जरूरत है।

कार्यक्रमी ने आठ माह से नहीं बांटा पोषाहार

भ्रांता सुप्रेरपुर। जलाला की प्रधान बिहू सिंह ने सौंडीपीओं से शिक्षायत करके अवकाश कराया था कि भ्रांता के अंगनवाड़ी केंद्र संचालिकों रीता देवी, सहायता कराया था जो 2023 से पोषाहार का वितरण नहीं किया है। सौंडीपीओं प्रीति भिलावरे ने मामले की जांच मुख्य सेविका तारा देवी को सौंपी थी। मुख्य सेविका की जांच में प्रधान सहित लाभार्थी अंशिता, ललिता, शालिनी आदि ने बताया कि उन्होंने पिछले नौ माह से पोषाहार नहीं मिल रहा है। मुख्य सेविका को केंद्र में आधा पोषाहार मौजूद मिला। लेकिन वह वितरण लायक नहीं बचा है। जांच रिपोर्ट के बाद सौंडीपीओं ने अंगनवाड़ी कार्यक्रमी की सेवा समास की संस्तुति की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अंगनवाड़ी की कार्यक्रमी का मानदेव पूर्व में ही रोक दिया गया था। सौंडीपीओं की सेवा समाप्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

चुनाव के दृष्टिगत हुआ एरिया डोमिनेशन

मैनपुरी / बरनाहल। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिनोज कुमार अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास तथा क्षेत्रीय कारहल के सफल पर्यवेक्षण में थाना अधीक्षक बरनाहल सुखबीर सिंह के मौसम सामान्य निर्वाचन पर रहते हुए एरिया डोमिनेशन

ऑपरेशन त्रिनेश: बढ़ रहा कारावा

कानपुर। शहर की हर गली, हर चौराहा और हर घर को कार्यक्रमी के नेटवर्किंग के द्वारा मैं लाने की पुलिस कमिशनर अधिक्षक कुमार की मुहिम में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। मंगलवार का अधीक्षक भारतीय शर्टरेंज मध्यसंघ के अध्यक्ष डॉ. संजय कपूर ने पुलिस कमिशनर से एकांप्रेशन कर भ्रांत कर रहे थे। एकांप्रेशन के लिए अपर ऑपरेशन त्रिनेश के बारे में जानकारी की चौराहे में लाने के बारे में जानकारी देते थे।



ममता बनर्जी पर भड़के एबीपी वार्कर्की कार्यक्रम

कानपुर। एबीपी के वार्कर्की कार्यक्रमी ने नमता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रमी ने टीएमसी नेताओं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिम बांगला में चल रहे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संसदीय बांगली के साथ शोषण के आरोप लगा रहे। पश्चिम बांगला की सीएम पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। मंगलवार को एबीपी के कार्यक्रमी ने कानपुर के पास कार्यक्रमी ने एकांप्रेशन के बाद वार्कर्की कार्यक्रमी को निर्देशित किया।

लूटपाट करने वाले घढ़े पुलिस के हथे

कानपुर। रायपुरा पुलिस ने रात के अंधेरे में लूटपाट करने वाले गंगे के दो सदस्यों को गिरफतार किया है। इन लूटों ने ऐसी ही एक बारादात जनवरी के महीने में भवनासी निवासी जगतीश शुक्ल के साथ की थी। दोसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने बताया कि इस मामले की पड़ताल कर रही पुलिस ने निर्माणाबाद निवासी अनुग्रह सोनी और आवास विकास कल्याणपुर निवासी राकेश कुमार को गिरफतार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूट के 5 मोबाइल, एक बांगा गाड़ी और अनदेशी बांगा टमार है। जबकि राकेश आठों चालक है और सुद्धारों का काम करता है लूटों ने कई बारादातें कबूली हैं।

कानपुर। पुलिस उपायुक्त पूर्वी के दिशा निर्देशन में ट्रॉफेजिक व्हार्ट दीना सोनार रसिज टैटी हासियतल तिराया थाना रेल बाजार पर अर्जेट रिस्पॉन्स डिलर की गई जिसमें थाना प्रभारी समेत 40 पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस दौरान सबको ब्रॉफ किया गया, साथ ही एटी-एयरट उपकरणों के साथ सभी मौजूद रहे। आमूज गेल करके किया गया।

कानपुर। पुलिस उपायुक्त पूर्वी के दिशा निर्देशन में ट्रॉफेजिक व्हार्ट दीना सोनार रसिज टैटी हासियतल तिराया थाना रेल बाजार पर अर्जेट रिस्पॉन्स डिलर की गई जिसमें थाना प्रभारी समेत 40 पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस दौरान सबको ब्रॉफ किया गया, साथ ही एटी-एयरट उपकरणों के साथ सभी मौजूद रहे। आमूज गेल करके किया गया।

तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी...

'नाजायज' इश्क में दोस्त ने बदला जेंडर, एक करोड़ रुपए फूंके, फिर बेवफाई पर फूंकी करा



● कार में आग लगाने की घटना पर हैटिंग गैर खुलासा

आशुतोष मिश्र 'रुद'

कानपुर। "तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं। किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी..."। कुछ इसी 'नाजायज' के अन्तर्गत 191 बोजूद मिले थे। जबकि मध्यांश भोजन रजिस्टर में प्रधानाध्यापक दिनेश चंद्र ने 303 छात्र छात्राओं को भोजन करना दर्शाया था। इसकी रिपोर्ट बीड़ीओं ने जिलाधिकारी राहुल पांडेय को भेजी थी। बीड़ीओं की इस कार्यवाही से शिक्षकों में हड्डकंप मचा हुआ है।

पैट्रोन ने बैवध विभाग जैंडर को आग लगाने की विवादित स्थिति की जांच की गई तो सामने आया कि कार मालिक अनूप कुमार शुक्ला के बैंडे विभाग जैंडर को इंदौर निवासी लड़के के बैंडे और एमपी निवासी दीप तनवानिया से नजदीकी थी। वैभव ने उससे शादी करने का झांसा दिया था। शर्त थी कि लिंग परिवर्तन करना पड़े। इसके बाद दीप ने करीब 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके डाल कर कार में आग लगाने की वारदात का 'आपरेशन निवेश' की जांच की गई। जबकि डाल करीब 40 लाख रुपए खर्च करके एपीएस बोर्ड सर्वजीरी और फेस सर्वजीरी को आग कर देने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद बोर्ड जैंडर को जारी रखने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे। जैंडर को जारी रखने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे।

पैट्रोन ने बैवध विभाग जैंडर को आग लगाने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे।

पैट्रोन ने बैवध विभाग जैंडर को आग लगाने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे।

पैट्रोन ने बैवध विभाग जैंडर को आग लगाने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे।

पैट्रोन ने बैवध विभाग जैंडर को आग लगाने की विवादित स्थिति की जांच की गई। इसके बाद दीप ने एक कारीब खड़े हो रहे थे।

उमेर के साथ ही वो फैसले न्यायपालिका के क्षेत्र में भी मील के पत्थर साक्षित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से जहां हर देशवासी को गौरवान्वित किया है। वहीं देशवासियों को न्यायपालिका के प्रति विश्वास को भी सुदृढ़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की पूरे देश में सपराहा हो रही है। देश के आम आदमी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह महसूस होने लगा कि हमारे देश में न्याय कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। हालांकि पिछले कई वर्षों से देश में न्यायपालिका को कमज़ोर करने के आरोप लग रहे थे। जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने झुकाव दिया है। 104 मार्च 2024 को बोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब इस उल्लेखनीय सदन में बोट दिया या सवाल पूछा तो संसदों वा विधायिकों को विधायिकारक के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधानीक पीठ ने सोमवार को अपना 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। मृत्यु न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस बोपत्रा, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिंह, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मोजे मिश्रा की संविधानीक पीठ ने कहा कि हम 1998 में लिए गए जस्टिस पींची नरसिंह के उस फैसले से सहमत नहीं हैं। जिसमें सासदों और विधायिकों को सदन में भाषण देने वा बोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट ली गई थी। 1998 में 5 जजों की संविधानीक पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता है कि उसने बाद में बोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस बात कोई सांसद घूस स्टीकर करता है। संविधान के अर्थात्काल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार-विमर्श का महौल बनाए रखने के लिए हैं। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है। जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में बोट देने वा खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है।

आज का इतिहास

1508-नासिरुद्दीन मुहम्मद हुम्यून का जन्म।
1775-रुद्रांग राव और अंगेजी के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर।
1902-सेन में महाशूर फूटबॉल कलब % मीड बलब% की स्थापना हुई।
1915-शांति निकेतन में महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठैरे परहली बार मिले।
1953-74 वर्ष की अग्नि में जोसेफ स्टालिन का विनाश।
1967-जासोफ स्टालिन की बैटी खेलताना भारत रिश्वत रस्सी दूतावास से होते हुए अमेरिका पहुंची।
1991-प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस्टरीना किया।
1992-भारतीय युद्धस्वार फूटबॉल मिजाज का जन्म।
2001-फिंजि में महेन्द्र चौधरी के खलाफ पार्टी में ही विद्रोह की स्थिति।
2003-अल्लीरिया का एक विमान तामारासेट में दुर्घटनाग्रस्त, 102 से भी अधिक यात्री मरे।
2004-उत्तर कोरिया का यूरेनियम आधारित कार्यक्रम होने से फिर इन्कार।
2008-राजस्थान से राजस्थान सांसद प्रधा बाबू को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सबरजीत की दया याचिका खारिज की।
2009-भारतीय यावसानों को तीन दशक तक अपनी सेवाएँ देने के बाद स्किंग-विंग लड़ाकू विमान मिग-23 ने अनिम्न उड़ान भरी।
2015-भारतीय राजनीतिज्ञ और विहार के मुख्यमंत्री रहे राम सुंदर दास का निधन।
2018-कॉनराड संगमा ने भारतीय राज्य मेघलाय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शायदी ली।

अदालत और सरकार में फैसले उपभोक्ता आयोग

डॉ. अंजय खेमरिया

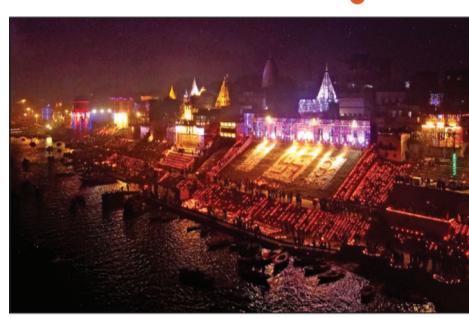
देश में उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर इन दिनों में एक विचारिता प्रधा नुमान के खिलाफ आयोगों को बोलता है कि जल्द ही सकारा इस पराया के प्रावधान को खत्म कर देंगी। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ परायिकों में बैठना पड़ा तो कोइंग को खिलाफ आयोगों को बोलता है कि जल्द ही सामान्य लोगों के लिए विचारिता के आदेश खुद को बोलता है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। शीर्ष अदालतें कानून के जीवनी प्रवर्तन के स्थान पर अनावश्यक रूप से आयोगों के गठन और उपभोक्ता आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ परायिकों में बैठना पड़ा तो कोइंग को खिलाफ आयोगों को बोलता है कि जल्द ही सकारा इस पराया के प्रावधान को खत्म कर देंगी। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। शीर्ष अदालतें कानून के जीवनी प्रवर्तन के स्थान पर अनावश्यक रूप से आयोगों के गठन और उपभोक्ता आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब हाईकोर्ट और जिला जाली के जब सामान्य लोगों के साथ अप्रतिक्रियाकारी आयोगों को लेकर जागरूकता का अभाव है। अलबता न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के लिए लिखित परायिकों के प्रावधान को जारी कर दिया था। विचारिता के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस विचारिता के अनुरूप पिछले साल दिए थे। अब



आध्यात्मिक-सांस्कृतिक नगरों से भी मिली आर्थिक संजीवनी



उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुट्ट हुई, तो यहां निवेश आना भी शुरू हुआ। हर सेक्टर में बड़ी-बड़ी कंपनियों के निवेश से रोजगार के लाखों अवसर सृजित हुए, तो यूपी से युवाओं के पलायन पर भी विराम लग गया। योगी सरकार ने विकास की श्रृंखला को महज औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि आध्यात्मिक-सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत संजोने पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया, नतीजन आज ऐसे शहर भी प्रदेश को भरपूर राजस्व उपलब्ध करा रहे हैं। अयोध्या हो या काशी, गोरखपुर, मथुरा-वृद्धावन हो या प्रयागराज, नैमिषारण्य हो या बौद्ध आध्यात्मिक स्थल, हर तीर्थ स्थल आज पर्यटकों का प्रमुख गंतव्य बन गया। प्रदेश सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए एनसीआर की तर्ज पर यूपी में राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) परियोजना को धरातल पर उतारा है। इसमें लखनऊ सहित आस-पास जनपदों में हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, निवेशक और तेजी से यूपी की ओर रुख करेंगे। ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाओं ने इन जनपदों को विशिष्ट पहचान दिलाने के अलावा अर्थ की संजीवनी भी प्रदान किया है। यूपीजीआईएस-23 के दौरान हुए रिकॉर्ड एमओयू के परिणामस्वरूप जीवीसी 4.0 में धरातल पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा।



वाणिजी

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
581	142903

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
19245	44215

निवेश का बना माहौल

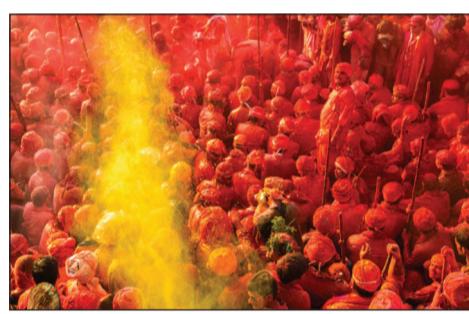
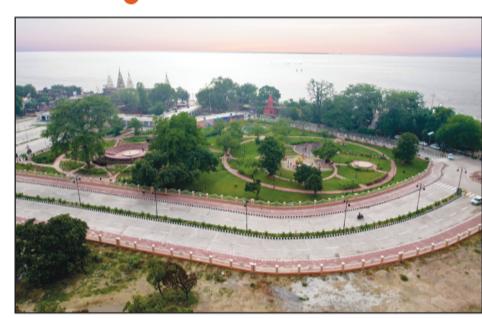
गोरखपुर में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। गोडा पूर्वाचल, नेपाल और सीमावर्ती बिहार की आर्थिक राजधानी है। यहां मार्केट तो ही, कामगारों की भी कोई कमी नहीं है। हमारी कंपनी 10 करोड़ रुपये के निवेश से पेपर डिस्पोजल यूनिट का विस्तार कर रही है।

-सुधांशु टिकरेवाल, उद्यमी, गोरखपुर

अयोध्या

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
508	145116

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
12915	25000



मथुरा

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
484	30235

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
16587	31680

हाल के वर्षों में सरकार ने शहरीकरण को काफी तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और शहर का विकास भी हुआ है। प्रयागराज के साथ मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ आदि जनपदों में रियल एस्टेट में 750 करोड़ रुपये के निवेश से आवासीय और कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स बनाये जायेंगे।

-सुनील सोलंकी, ओमेक्स लिमिटेड, प्रयागराज

गोरखपुर

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
630	183738

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
17313	37000



प्रयागराज

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
460	63618

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
13227	25000

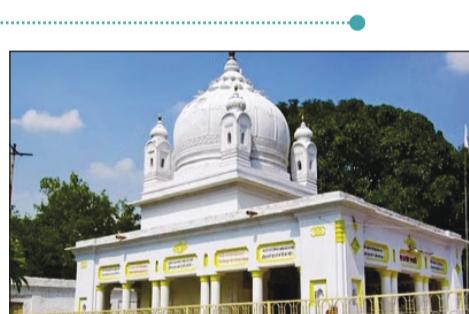
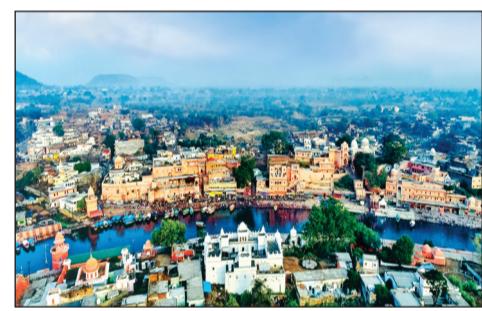
सीतापुर में भी निवेश का माहौल बना है। उद्योगों को राहत दी जा रही है इससे जनपदों के विकास को पंख लगेंगे। स्थानीय स्तर पर उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हुने वाले कच्चे माल को लेकर सहूलियत होगी। पर्यटन की दृष्टि से नैमित्य में बहुत संभावनाएं हैं।

-अंजीत कुमार सिंह, उद्यमी, सीतापुर

चित्रकूट

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
280	67422

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
7147	7000



मांतकबीनगर

यूपीजीआईएस-2023	
परियोजनाएं	एमओयू करोड़ रु. में
92	5480

जीवीसी-4.0	
निवेश करोड़ रु. में	रोजगार
1872	3652

प्रमुख निवेशक कंपनियां

अयोध्या

हाउस ऑफ अभिनंदन लोडा (रियल स्टेट) 3000 करोड़ रुपये का निवेश, 100 लोगों को रोजगार पक्का लिमिटेड (पेपर मैन्युफैक्चरिंग मर्शिन) 550 करोड़ रुपये का निवेश, 600 लोगों को रोजगार

मीरजापुर

डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग)

3000 करोड़ रुपये का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार

सीतापुर

सेंचुरी प्लाइबर्ड इंडिया लिमिटेड (लकड़ी)

1500 करोड़ रुपये का निवेश, 3000 लोगों को रोजगार

ग्रीनलैंस साउथ लिमिटेड

(लकड़ी/एमडीएफ) 1500 करोड़ रुपये का निवेश,

2000 लोगों को रोजगार

मथुरा

आईएफपी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि.

(रिफाइनरी)

1100 करोड़ रुपये का निवेश, 700 लोगों को रोजगार

केशव पाल्केंशेस प्राइवेट लिमिटेड

(स्टेशनरी गुड्स, इलेक्ट्रिक आइटम, लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग)

1250 करोड़ रुपये का निवेश, 10000 लोगों को रोजगार

मुजफ्फरनगर

भारतीय बेवरेज प्रा.लि. (बेवरेज)